दैनिक
# न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

**आवश्यक सूचना**

**आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।**

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, गुरुवार 16 दिसंबर 2021 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-04, अंक- 79

## महत्वपूर्ण एवं खास

### चॉपर क्रैश में जख्मी हुए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का हुआ निधन

**नई दिल्ली (आरएनएस)।** बीते सप्ताह तमिलनाडु के नीलगिरि जिले में सीडीएस जनरल बिपिन रावत के चॉपर क्रैश में जख्मी हुए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का भी निधन हो गया है। इंडियन एयर फोर्स के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह अकेले ऐसे सदस्य थे, जो घटना के बाद जीवित मिले थे और उन्हें बचाने के तमाम प्रयास किए। लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशें बेकार साबित हुईं और आज उन्होंने दम तोड़ दिया। सूत्रों के मुताबिक हेलिकॉप्टर क्रैश हादसे में उनका शरीर 90 फीसदी से ज्यादा जल चुका था और उनकी हालत लगातार गंभीर बनी हुई थी। हाल ही में उन्हें इलाज के लिए चेन्नै से बेंगलुरु के सैन्य अस्पताल में शिफ्ट किया गया था। पूरे एक सप्ताह तक डॉक्टर उनके जीवन को बचाने के लिए मशक्कत करते रहे, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। वरुण सिंह के निधन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी दुख और संवेदना व्यक्त की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ने पूरे गर्व, पराक्रम और पेशेवर क्षमता के साथ देश की सेवा की थी। उनके निधन से मैं बेहद दुखी हूं। देश के लिए उनके अमूल्य योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। उनके परिवार और मित्रों के प्रति मेरी संवेदनाएं।

### दलाई लामा से मिलेंगे जो बाइडेन? तिब्बत पर कड़ा रुख अपनाएगा अमेरिका

**न्यूयॉर्क।** अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों ने राष्ट्रपति जो बाइडेन और तिब्बती आध्यात्मिक धर्मगुरु दलाई लामा के बीच बैठक की अपील की है। कहा है कि तिब्बत को लेकर अमेरिकी कानूनों को पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए और तिब्बत को चीन का हिस्सा कहने की प्रथा खत्म होनी चाहिए। अमेरिकी कांग्रेस के 60 से अधिक सदस्यों ने नए सीनेट में यह बात कही है। अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उजरा जेया को लिखे गए चिट्ठी से यह साफ है कि कांग्रेस अब तिब्बत मसले पर फोकस कर रही है। ऐतिहासिक रूप से आजाद देश तिब्बत जिस पर चीन ने 60 से अधिक सालों से क्रूरता से कब्जा किया हुआ है, अमेरिका लगातार तिब्बत के समर्थन में रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विदेश विभाग में तिब्बती मसलों के लिए स्पेशल कोआर्डिनेटर के रूप में जेया की जल्द ही नियुक्ति की जा सकती है। तिब्बत के लिए अभियान चलाने वाले समूहों ने चिट्ठी को लेकर कहा है कि कांग्रेस को उम्मीद है कि बाइडेन प्रशासन तिब्बती लोगों का समर्थन करने के लिए जल्द ही सार्थक रूप से काम करेगा। इंटरनेशनल कैम्पेन फॉर तिब्बत ने 38 सीनेटर और 27 प्रतिनिधियों को तिब्बत मसले पर साथ आने के लिए शुक्रिया कहा है।

### रूस ने यूक्रेन सीमा पर तैनात किया खतरनाक बुख

**मॉस्को।** रूस ने यूक्रेन सीमा के पास बुख नाम का एक खास मिसाइल सिस्टम तैनात किया है. माना जाता है कि 2014 में इसी से मलेशियन एयरलाइंस का विमान गिराया गया था. इस प्लेन क्रैश के दोषी को कैसे खोजा गया. जानिए इस रिपोर्ट में.12 दिसंबर को जी7 समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक में रूस और यूक्रेन के तनाव पर मुख्य रूप से चर्चा हुई. बैठक में रूस को चेतावनी दी गई कि यूक्रेन के खिलाफ किसी भी तरह की सैन्य आक्रामकता के गंभीर नतीजे होंगे. अंतरराष्ट्रीय कानूनों में सीमा बदलने के इरादे से किसी भी तरह बल प्रयोग की सख्त मनाही है. रूस ने यूक्रेन सीमा के पास बड़ी संख्या में सैनिक और सैन्य उपकरण तैनात कर दिए हैं. कई हल्कों में इसे यूक्रेन पर हमले की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है. क्या है क्रीमिया एनेक्सेशन? 2014 में रूस ने यूक्रेन के इलाके क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था. पश्चिमी देश तब क्रीमिया पर हुए कब्जे को तो नहीं रोक पाए थे लेकिन उन्होंने इतना किया कि रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए. पश्चिमी देश नहीं चाहते कि रूस किसी भी सूरत में 2014 जैसी घटना दोहराए. इसीलिए वे रूस को लगातार चेतावनी दे रहे हैं. पिछले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात कर यूक्रेन पर तनाव घटाने की कोशिश की. लेकिन ये तमाम कोशिशें रूस की आक्रामकता कम नहीं कर पाई हैं. क्या है बुख से जुड़ा विवाद? रूस ने यूक्रेन सीमा के पास एक खास मिसाइल सिस्टम तैनात किया है.

# मंत्रिमंडल ने 2021-26 के लिये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के क्रियान्वयन को दी मंजूरी

**नई दिल्ली (आरएनएस)।** प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आज 93,068 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ 2021-26 के लिये प्रधानमंत्री कृषि संचाई योजना (पीएकेएसवाई) के क्रियान्वयन को मंजूरी दे दी है।

सीसीईए ने राज्यों के लिये 37,454 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता तथा पीएमकेएसवाई 2016-21 के दौरान सिंचाई विकास के लिये भारत सरकार द्वारा लिये गये ऋण को चुकाने के सम्बंध में 20,434.56 करोड़ रुपये मंजूर किये हैं।

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीबी), हर खेत को पानी (एचकेकेपी) और भूमि, जल व अन्य विकास घटकों को 2021-26 में जारी रखने को भी मंजूरी दी गई।

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, केंद्र सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य सिंचाई परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। एआईबीपी के अंतर्गत 2021-26 के दौरान कुल अतिरिक्त सिंचाई क्षमता को 13.88 लाख हेक्टेयर तक करना है। चालू 60 परियोजनाओं को पूरा करने पर ध्यान देने के अलावा, जिसमें उनसे सम्बंधित 30.23 लाख हेक्टेयर कमान क्षेत्र विकास भी शामिल है, अतिरिक्त परियोजनाओं को भी शुरू किया जा सकता है। जनजातीय इलाकों और जल्दी सूखे का सामना करने वाले इलाकों की परियोजनाओं कोशामिल करने के मानदंडों में ढील दी गई है।

रेणुकाजी बांध परियोजना (हिमाचल प्रदेश) और लखवार बहुउद्देश्यीय परियोजना (उत्तराखंड) नामक दो राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिये 90 प्रतिशत केंद्रीय वित्तपोषण का प्रावधान किया गया है। दोनों परियोजनाएं यमुना बेसिन में भंडारण की शुरूआत करेंगी, जिससे यमुना बेसिन के ऊपरी हिस्से के छह राज्यों को फायदा पहुंचेगा। साथ ही दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश, हरियाणा और राजस्थान को जलापूर्ति होगी तथा यमुना के उद्धार की दिशा में प्रगति होगी।

हर खेत को पानी (एचकेकेपी) का उद्देश्य है कि खेतों तक पहुंच में इजाफा हो और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य भूमि का विस्तार हो। एचकेकेपी के तहत लघु सिंचाई और जल स्रोतों के उद्धार-सुधार-बहाली, पीएमकेएसवाई के घटक हैं तथा इनका उद्देश्य है कि अतिरिक्त 4.5 लाख हेक्टेयर रकबे को सिंचाई के दायरे में लाना। जल स्रोतों के उद्धार के महत्त्व के मद्देनजर, मंत्रिमंडल ने शहरी और ग्रामीण इलाकों में जल स्रोतों को दोबारा जीवित करने के लिये वित्तपोषण को मंजूरी दी है। इस योजना में उन्हें शामिल करने के मानदंडों का विस्तार किया गया है तथा केंद्रीय सहायता को आम क्षेत्रों के हवाले से 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत किया गया है। इसके अलावा एचकेकेपी के भूजल घटक को भी 2021-22 के लिये अस्थायी रूप से मंजूर किया गया। इसका लक्ष्य है 1.52 लाख हेक्टेयर भूमि के लिये सिंचाई क्षमता विकसित करना।

वॉटरशेड विकास घटक का लक्ष्य है वर्षा जल द्वारा सिंचित इलाकों का विकास करना। इसके लिये मिट्टी और जल संरक्षण, भूजल की भरपाई, मिट्टी बहने को रोकना तथा जल संरक्षण व प्रबंधन सम्बंधी विस्तार गतिविधियों को प्रोत्साहित करना।

## किसान लौटे लेकिन ट्रैफिक के लिए अभी नहीं खुल पाएंगे गाजीपुर और सिंघु बॉर्डर

**नई दिल्ली (आरएनएस)।** सरकार के साथ समझौता होने के बाद एक साल से जारी किसान आंदोलन स्थगित हो चुका है और किसानों ने दिल्ली बॉर्डर खाली कर दिए हैं। भले ही किसान लौट गए हों लेकिन गाजीपुर और सिंघु बॉर्डर पर फिलहाल ट्रैफिक शुरू नहीं होने जा रहा है। नेशनल हाइवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा है कि दिल्ली और गाजियाबाद को जोड़ने वाले गाजीपुर बॉर्डर और नेशनल हाईवे 44 पर सिंघु बॉर्डर किसानों के आंदोलन की वजह से पिछले करीब एक साल से बंद थे और इन्हें फिर से चालू करने में कुछ और दिन लगेंगे, ये जनवरी में ही फिर से ट्रैफिक के लिए खोले जा सकेंगे।

किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने भी कुछ पक्के बैरिकेड बना दिए थे उन्हें हटाने में वक़्त लग रहा है। साथ ही इन्हें हटाने के बाद पूरे इलाके का निरीक्षण किया जाएगा इसी के बाद इन्हें आम लोगों के लिए खोला जा सकेगा। एनएचएआई के अधिकारियों ने कहा कि एनएच-24, एनएच-9 और एनएच-44 पर दोनों तरफ के हिस्सों के निरीक्षण का कार्य 15 दिसंबर के बाद से शुरू होगा। किसानों ने आज ये बॉर्डर पूरी तरह खाली कर दिए हैं और हाइवें की टीमें यहां काम में लग गई हैं। इसके बाद दोनों तरफ के हिस्सों को पूरी तरह साफ करने में 2 हफ्तों का समय लगेगा।

एनएचएआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि किसान जब दोनों तरफ के हिस्सों से पूरी तरह हट जाएंगे तब उसके बाद निरीक्षण का काम हम शुरू करेंगे। हमारी टीम एनएच के नष्ट हुए हिस्सों का निरीक्षण करेगी। इसके बाद इसकी रिपेयरिंग का काम शुरू होगा।

## नाले में गिरी बस, 9 लोगों की मौत, कुछ लोगों के घायल होने की भी आशंका

**एलुरु (आरएनएस)।** आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के जंगारेड्डीगुडेम में बुधवार को हुई भीषण सड़क दुर्घटना में राज्य पथ परिवहन निगम (एपीएसआरटीसी) की बस के जलेरू नाले में गिरने से नौ यात्रियों की मौत हो गई और नौ अन्य घायल हो गए। पुलिस ने कहा कि अश्वरावपेट से जंगारेड्डीगुडेम जा रही बस में 40 से अधिक यात्री सवार थे।

पुलिस के मुताबिक बस रेलिंग से टकराने के बाद पुल से 30 फुट ऊंचाई से नाले में जा गिरी, जिसके कारण यह हादसा हुआ। पास के मछुआरों और राहगीरों ने कुछ यात्रियों को बचाया लेकिन तब तक पांच महिलाओं सहित नौ यात्रियों की मौत हो चुकी थी। मृतकों में बस चालक चिन्ना राव भी शामिल है। सभी शवों को दुर्घटनाग्रस्त बस से बाहर निकाल लिया गया। अब तक चार यात्रियों की पहचान चिन्ना राव, पी दुर्गा, वरलक्ष्मी और ए मधुबाबू के रूप में हुई है। घायल लोगों को जंगारेड्डीगुडेम के सरकारी सामान्य अस्पताल (जीजीएच) में स्थानांतरित कर दिया गया है। आरटीसी अधिकारियों ने कहा कि दुर्घटना के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। इस बीच, मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने नौ आरटीसी बस यात्रियों की मौत पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने मृतकों के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपये सहायता राशि देने की घोषणा की है। रेड्डी ने पश्चिम गोदावरी जिला कलेक्टर से बात की और घायलों को बेहतर उपचार प्रदान करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया।

## संसद ने सीबीआई, ईडी निदेशक का कार्यकाल बढ़ाने वाले विधेयक को दी मंजूरी

**नई दिल्ली (आरएनएस)।** संसद ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशकों के कार्यकाल को पांच साल तक बढ़ाने वाले विधेयकों को पारित कर दिया है। राज्यसभा में विपक्ष के बहिर्गमन के बीच ध्वनि मत से विधेयक को पारित कर दिया गया।

इसके साथ ही एजेंसी के निदेशकों के कार्यकाल की सीमा वर्तमान बढ़ाकर पांच साल तक करने के प्रावधान का रास्ता साफ हो गया है। लोकसभा में यह विधेयक नौ दिसंबर को पारित हो चुका है। केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021 और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (संशोधन) विधेयक, 2021 - दोनों को 9 दिसंबर को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था।

कार्मिक और प्रशिक्षण राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह द्वारा प्रस्ताव पेश किए जाने के तुरंत बाद, विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने 12 सदस्यों के निलंबन का मुद्दा उठाने की मांग की, लेकिन उपसभापति ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया और विरोध में विपक्षी सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन (बाहर चले जाना) किया। विपक्ष के बहिर्गमन के बाद बहस के दौरान, जनता दल-यूनाइटेड के सदस्य राम नाथ ठाकुर ने बिल का समर्थन करते हुए, बिहार में 46 साल से लंबित एक हत्या की जांच का एक उदाहरण भी दिया, और साथ ही आग्रह किया कि एक निश्चित कार्यकाल भी होना चाहिए जिसके भीतर जांच पूरी की जाए। तमिल म/नीला कांग्रेस के नेता जी. के. वासन, एजीपी के बीरेंद्र प्रसाद वैश्य, भाजपा के बृजलाल, वाईएसआरसीपी के पिल्ली सुभाष चंद्र बोस ने भी विधेयकों के समर्थन में बात की। भाजपा सदस्य सुरेश प्रभु ने संस्थानों और उन संस्थानों को चलाने वाले लोगों के महत्व पर जोर दिया। कानून संसद द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन कार्यान्वयन संस्थानों द्वारा किया जाता है और उस संस्था को चलाने वाले व्यक्तियों का सही होना जरूरी है। एक कार्यप्रणाली की आवश्यकता होती है। उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग और ईडी की भूमिका के बारे में भी बताया। भाजपा के सुशील कुमार मोदी ने भ्रष्टाचार के खतरे से छुटकारा पाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के बारे में विस्तार से बात की और बताया कि कैसे प्रत्यक्ष हस्तांतरण लाभों ने पारदर्शिता के लिए किए गए उपायों के कारण वास्तविक लाभार्थियों को सीधे पैसा सुनिश्चित किया है।

## वंदे भारतम् फाइनल प्रतियोगिता का 19 दिसंबर को नई दिल्ली में होगा आयोजन

**नई दिल्ली (आरएनएस)।** उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम ज़ोनों के 949 नृत्य कलाकारों के 73 समूह'वंदे भारतम्-नृत्य उत्सव' के ग्रैंड फिनाले में पहुंच गये हैं। यह अखिल भारतीय नृत्य प्रतियोगिता है, जिसे आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किया जा रहा है। फाइनल 19 दिसंबर, 2021 को नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम प्रेक्षागृह में होगा। रक्षा मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय ने आजादी के अमृत महोत्सव के क्रम में 'वंदे भारतम्-नृत्य उत्सव' की शुरुआत करने की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाना है। यह एक अनोखी पहल है, जो जनभागीदारी पर आधारित है। इसका मुख्य लक्ष्य है देशभर से सर्वोच्च नृत्य प्रतिभाओं का चयन करना तथा उन्हें गणतंत्र दिवस परेड 2022 के दौरान अपनी कला का प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान करना।

ग्रैंड फिनाले में नृत्य कलाकार इस सर्वोच्च सम्मान के लिये प्रतिस्पर्धा करेंगे। ऐसा अवसर जीवन में यदा-कदा ही मिलता है, जिसका लाभ उठाते हुये वे गणतंत्र दिवस परेड में अपनी प्रतिभा दिखायेंगे। इस परेड को न सिर्फ भारत, बल्कि पूरी दुनिया में देखा जाता है।

दो सौ से अधिक टीमों में से 2400 से अधिक प्रतिभागियों को जोनल स्तरीय प्रतियोगिता के लिये चुना गया था, जहां 104 ग्रुपों ने विद्वान ज्यूरी के समक्ष अपनी नृत्य प्रतिभा प्रदर्शित की थी। प्रतिभागी समूहों नेकई नृत्य विधाओं का प्रदर्शन किया। इन विधाओं में शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, जनजातीय नृत्य और मिला-जुला नृत्य शामिल था। देशभर की प्रतिभाओं और रंगारंग पोशाकों का संयोजन देखने को मिला। समाज के सभी वर्गों ने पूरे हर्षोल्लास से हिस्सा लिया तथा सभी वर्गों ने एक भारत, श्रेष्ठ भारत की भावना को बलवती बनाया।

वंदे भारतम् प्रतियोगिता 17 नवंबर को जिला स्तर पर शुरू हुई थी। इस दौरान 323 समूहों में 3,870 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। जो जिला स्तरीय प्रतियोगिता में सफल रहे, उन्हें 30 नवंबर, 2021 को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का अवसर मिला। वहां 20 से अधिक वर्चुअल आयोजन हुये। यह आयोजन चार दिसंबर, 2021 तक, यानी पांच दिन चला। राज्य स्तर पर 300 समूहों को चुना गया, जिनमें तीन हजार से अधिक नृत्य कलाकार/प्रतिभागी थे। इस तरह एक महीने तक आयोजन में सभी आकांक्षी कलाकारों ने अपनी प्रतिभा दिखाई और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिये प्रदर्शन किया।

## गडकरी ने ओडिशा, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में निर्माण, पुनर्वास और परियोजनाओं में सुधार की दी मंजूरी

**नई दिल्ली (आरएनएस)।** केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ओडिशा के केसिंगा में एनएच-201 (वर्तमान में एनएच-26) के किमी 176 पर समपार संख्या (लेवल क्रॉसिंग) आरवी-172 के बदले भूमि अधिग्रहण सहित 4 लेन के केसिंगा आरओबी निर्माण की मंजूरी दे दी है। इस पर 324.09 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। ट्वीट्स की एक श्रृंखला में मंत्री ने सूचित किया कि आंध्र प्रदेश में नियमित तौर पर यात्रा किए जाने वाले एनएच 30 के राजमार्ग से सटे राजमार्ग के एक हिस्से 170+700 किलोमीटर से 234+567 (डिजाइन चौ.) के पुनरूद्धार और सुधार को 388.70 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है।

आंध्र प्रदेश में ईपीसी मोड पर एनएच-42 के मुलकालाचेरुवु के मदनपल्ले खंड के साथ 2 लेन से 2/4 लेन के पुनरूद्धार और सुधार को 480.10 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया है।

मध्य प्रदेश राज्य में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सीआरआईएफ योजना के तहत 600.13 किलोमीटर लंबाई के 23 परियोजना कार्यों के विकास को 1814.90 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया है।

# कैबिनेट ने भारत में सेमीकंडक्टरों और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए कार्यक्रम को दी मंजूरी

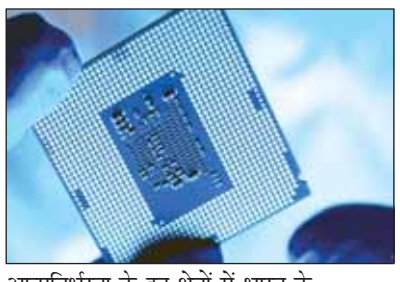

**नई दिल्ली (आरएनएस)।** प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने और भारत को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एवं विनिर्माण के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से, देश में सेमीकंडक्टरों और डिस्प्ले इकोसिस्टम के विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम को मंजूरी दी है। यह कार्यक्रम सेमीकंडक्टरों और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग के साथ-साथ डिजाइन के क्षेत्र में कंपनियों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी प्रोत्साहन पैकेज प्रदान करके इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियों के निर्माण में एक नए युग की शुरुआत करेगा। यह सामरिक महत्व तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता के इन क्षेत्रों में भारत के प्रौद्योगिकीय नेतृत्व के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा।

सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स की नींव हैं, जो उद्योग 4.0 के तहत डिजिटल परिवर्तन के अगले चरण की ओर आगे बढ़ा रहे हैं। सेमीकंडक्टरों और डिस्प्ले प्रणालियों का उत्पादन बहुत जटिल तथा प्रौद्योगिकी की अधिकता वाला क्षेत्र है, जिसमें भारी पूंजी निवेश, उच्च जोखिम, लंबी अवधि और पेबैक अवधि तथा प्रौद्योगिकी में तेजी से बदलाव शामिल हैं और इसके लिए अत्यधिक एवं निरंतर निवेश की आवश्यकता होती है। यह कार्यक्रम पूंजी सहायता और प्रौद्योगिकीय सहयोग की सुविधा प्रदान करके सेमीकंडक्टरों और डिस्प्ले प्रणाली के उत्पादन को बढ़ावा देगा।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य सिलिकॉन सेमीकंडक्टर फैब, डिस्प्ले फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टरों/सिलिकॉन फोटोनिक्स/सेंसर (एमईएमएस सहित) फैब, सेमीकंडक्टर पैकेजिंग (एटीएमपी/ओएसएटी), सेमीकंडक्टर डिजाइन के काम में लगी हुई कंपनियों/संघों को आकर्षक प्रोत्साहन सहायता प्रदान करना हैं।

भारत में सेमीकंडक्टरों और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए निम्नलिखित व्यापक प्रोत्साहनों को मंजूरी दी गई है-

सेमीकंडक्टर फैब और डिस्प्ले फैब- भारत में सेमीकंडक्टर फैब तथा डिस्प्ले फैब की स्थापना की योजना उन आवेदकों को परियोजना लागत के 50 प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जो पात्र पाए गए हैं और जिनके पास प्रौद्योगिकी के साथ-साथ इस प्रकार की अत्यधिक पूंजी वाली तथा संसाधन केंन्द्रित परियोजनाओं के निष्पादन की क्षमता है। भारत सरकार देश में कम से कम दो ग्रीनफील्ड सेमीकंडक्टर फैब तथा दो डिस्प्ले फैब स्थापित करने के लिए आवेदनों को मंजूरी देने हेतु भूमि, सेमीकंडक्टर ग्रेड जल, उच्च गुणवत्ता वाली बिजली, लॉजिस्टिक्स तथा अनुसंधान प्रणाली के रूप में आवश्यक बुनियादी ढांचे वाले हाई-टेक क्लस्टर स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करेगी।

सेमी-कंडक्टर प्रयोगशाला (एससीएल) - केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह भी मंजूरी दे दी है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सेमी-कंडक्टर प्रयोगशाला (एससीएल) के आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। यह मंत्रालय ब्राउनफील्ड फैब संयंत्र के आधुनिकीकरण के लिए एक वाणिज्यिक फैब पार्टनर के साथ एससीएल के संयुक्त उद्यम की संभावना तलाशेगा।

कंपाउंड सेमीकंडक्टर/सिलिकॉन फोटोनिक्स/सेंसर (एमईएमएस सहित) फैब तथा सेमीकंडक्टर एटीएमपी/ओएसएटी इकाइयां- भारत में कंपाउंड सेमीकंडक्टर/सिलिकॉन फोटोनिक्स/सेंसर (एमईएमएस सहित) फैब्स और सेमीकंडक्टर एटीएमपी/ओएसएटी संयंत्रों की स्थापना हेतु योजना के तहत स्वीकृत इकाइयों को पूंजीगत व्यय की 30 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।